गुजरात में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना का पूरा किया जाना

4012. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रही बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 10 वृहद, 41 मध्यम और 11 आधुनिकीकरण/पुरूद्धार सिंचाई परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः लगभग 9542 करोड़ रुपये 703 करोड़ रुपए तथा 241 करोड़ रुपए है और जिनसे क्रमशः 21.18 लाख हैक्टेयर, 1.97 लाख हैक्टेयर एवं 41,000 हैक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गयी है, आठवीं योजना में आगे लाई गई हैं।

(ख) और (ग) कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई, योजना आयोग ने राज्य सरकार के आठवीं योजना प्रस्तावों में इन परियोजनाओं के लिए 3325 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(घ) मार्च, 1992 तक वृहद, मध्यम और आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार सिंचाई परियोजनाओं पर क्रमशः लगभग 2692 करोड़ रुपए, 570 करोड़ रुपए और 213 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इनसे क्रमशः 2.24 लाख हेक्टेयर, 1.15 लाख हेक्टेयर और 40,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। आठवीं योजना का जोर अधिकांश निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने पर है।

गुजरात में नहरों का निर्माण

4013. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में नहरें बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, निर्माण, वित्तपोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारें द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य योजना में उनको सम्मिलित करने के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान करने से पहले केवल बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जांच करती है। नियोजित युग के प्रारंभ से अब तक गुजरात सरकार ने लगभग 33 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता सृजित की है। योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए राज्य सरकार के सिंचाई क्षेत्र हेतु 3756 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। राज्य सरकार का आठवीं योजना का लक्ष्य लगभग 11 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का है।

Polavaram Multipurpose Project

4014. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Andhra Pradesh submitted a complete modified project Report on the Polavaram Multipurpose project to the CWC;

(b) what is the status of the Project; and

(c) whether it is also a fact that the Government of Andhra Pradesh urged the Government of India to take up this Project as a National Project?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (Shri V.C. Shukla): (a) and (b) No. Sir, While in July, 1990 the State Government of Andhra Pradesh submitted only up dated estimate of the earlier report without taking into consideration the observations and deficiencies pointed out by the Central Water Commission, in July 1992 the State Government submitted hydrology chapter for finalisation in the first instance. After examination hydrological series has been finalised by Central Water Commission and the State Government has been advised to finalises irrigation planning to